

प्राधिकरण बिल्डरों से जब्त प्लैटों की जल्द शुरू करेगा नीलामी नोएडा स्थित गुलमोहर सोसाइटी के बिल्डर पर 30 करोड़ रुपये का बकाया, पांच प्लैट होंगे नीलामी: एसीईओ

पायनियर समाचार सेवा | नोएडा

नोएडा प्राधिकरण डिफॉल्टर बिल्डरों की सील हो चुकी पर्याप्त योजनाओं को जल्द नीलाम करने जा रहा है। इसको लेकर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। नोएडा प्राधिकरण ने पहली बार एक सोसाइटी के पांच प्लैट को ई-नीलामी करने की योजना निकाली है।

इन सभी प्लैटों को नोएडा प्राधिकरण जल्द नीलाम करेगा। नोएडा प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रभाष यादव ने बताया कि सेक्टर-44 में गुलमोहर सोसाइटी है। इस बिल्डर पर प्राधिकरण के करीब 30 करोड़ रुपये बकाया है।

कई बार नोटिस देने के बाद भी बिल्डर द्वारा बकाया राशि जमा नहीं की जा रही है।



को हैंडओवर भी की जा चुकी है। एओए अब इन प्लैटों को नीलाम करने की ने भी बकाया राशि प्राधिकरण के कार्यालय योजना प्राधिकरण ने तैयार की है। पांच प्लैट में जमा करने से मना कर दिया था। ऐसे में को नीलाम करने की योजना नोएडा है।

टॉप-20 डिफॉल्टरों के आवंटन होंगे निरस्त

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ईकोटेक 16 में पेवर हायसिंग स्कीम लांच करेगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ने योग्यिक विभाग की समीक्षा करते हुए इस बाबत निर्देश दिए हैं। उन्होंने टॉप-20 डिफॉल्टरों के आवंटन भी तकाल निरस्त करने को बताया है। सीईओ और माहेश्वरी ने कहा कि आवंटियों ने अभी तक न तो तयार लगाया है और न ही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का योग्य और इंतजार न करें। आर आवंटियों को आंतिम नोटिस भेजी गई है तो समय सीमा पूरी होने ही उनके आवंटन निरस्त कर दिए जाएं। प्लैटों को कब्जे में लेकर स्कीम के जरिए अन्य निवेशकों को आवंटित करें, ताकि उन खूबीदों पर उत्थान लग सकें और युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें। बैठक में प्राधिकरण के एसीईओ आनंद वर्धन, एसेसडी विशु राजा सहित अन्य मौजूद रहे।

प्राधिकरण जल्द लेकर आ रहा है। नीलामी पैन रिलाईट्स की पैन ओसिस सोसायटी के द्वारा जो भी खरीदार सबसे ऊंची बोली एक निर्माणाधीन टावर को सील किया लगाया। उनको प्लैट आवंटित किया गया है। उनके खिलाफ बकाया वसूली करने जाएगा। वहाँ, बकाया नहीं देने वाले बिल्डरों के लिए आरसी जारी की गई है। इस पर लगातार प्राधिकरण की तरफ से सख्त परियोजना पर प्राधिकरण के 470 बरती जा रही है। हाल ही में सेक्टर-70 स्थित करोड़ रुपये बकाया है।

कार्यकारिणी चुनाव को लेकर आपसी सहमति का प्रयास

पायनियर समाचार सेवा | गाजियाबाद

निगम बोर्ड की पहली बैठक 22 या 23 जून को हो जाएगी। बोर्ड बैठक में ही कार्यकारिणी के 12 सदस्यों का चुनाव आपसी सहमति से हो जाए। क्योंकि यदि चुनाव की नीति आई तो संख्या बल के आधार पर भाजपा और विपक्ष दलों में आपसी सहमति पर चर्चा चल रही है।

नगर निगम आपसी सहमति पर चर्चा चल रही है। बैठक बुलाने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। बोर्ड

विपक्ष की भी भागीदारी होनी चाही रही। उनका मानना है कि नगर निगम में सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर काम की पहली बैठक किसी भी सुरक्षा में 23 जून तक होनी चाही है। उनको वित्तीय आरियों का प्रतिविधियां और पुनर्निर्माण तथा प्रतिविधि वित्त प्रबन्धन अधिनियम, 2002 के धारा 13 (2) के अन्य निवारणी विधि के एक सूचना उनके द्वारा बैठक के उपलब्ध कराया गया, उनके अधिनियम जारी कर दिया गया। इस सार्वजनिक सूचना द्वारा सूचित किया जा रहा है।

जून से पहले शासन के अनुमोदन के लिए भेजा जाना

सार्वजनिक सूचना

पंजी. कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, लैंडमार्क, रेस कोर्ट सॉफ्टकॉर्न,

कापार्ट-1 कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टावर, बान्दा-कूला कॉम्प्लेक्स, बान्दा (ई), यूपी-400051

शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टावर, बान्दा-कूला कॉम्प्लेक्स, बान्दा (ई), यूपी-400051

शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टावर, सेक्टर-11, काम्प्लेक्स सेंटर एस.एस. टावर, सेक्टर-8, रोहिंगी, नई दिल्ली-110085

एस्टेट्स शूपानी द्वारा भी होती है कि निर्माणित कर्जदारी/रोड एंपैक्स द्वारा नियम 5 के उप-नियम (2क) के साथ परियोजना की योजना नहीं की उप-धारा (4) के तहत सामने आयी है।

नगर निगम आपसी सहमति पर चर्चा चल रही है। बैठक बुलाने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। बोर्ड

विपक्ष की भी भागीदारी होनी चाही रही। उनका मानना है कि नगर निगम में सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर काम की पहली बैठक किसी भी सुरक्षा में 23 जून तक होनी चाही है। उनको वित्तीय आरियों का प्रतिविधियां और पुनर्निर्माण तथा प्रतिविधि वित्त प्रबन्धन अधिनियम, 2002 के धारा 13 (2) के अन्य निवारणी विधि के एक सूचना उनके द्वारा बैठक के उपलब्ध कराया गया, उनके अधिनियम जारी कर दिया गया। इस सार्वजनिक सूचना द्वारा सूचित किया जा रहा है।

जून से पहले शासन के अनुमोदन के लिए भेजा जाना

सार्वजनिक सूचना

पंजी. कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, लैंडमार्क, रेस कोर्ट सॉफ्टकॉर्न,

कापार्ट-1 कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टावर, बान्दा-कूला कॉम्प्लेक्स, बान्दा (ई), यूपी-400051

शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टावर, बान्दा-कूला कॉम्प्लेक्स, बान्दा (ई), यूपी-400051

शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टावर, सेक्टर-11, काम्प्लेक्स सेंटर एस.एस. टावर, सेक्टर-8, रोहिंगी, नई दिल्ली-110085

एस्टेट्स शूपानी द्वारा भी होती है कि निर्माणित कर्जदारी/रोड एंपैक्स द्वारा नियम 5 के उप-नियम (2क) के साथ परियोजना की योजना नहीं की उप-धारा (4) के तहत सामने आयी है।

नगर निगम आपसी सहमति पर चर्चा चल रही है। बैठक बुलाने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। बोर्ड

विपक्ष की भी भागीदारी होनी चाही रही। उनका मानना है कि नगर निगम में सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर काम की पहली बैठक किसी भी सुरक्षा में 23 जून तक होनी चाही है। उनको वित्तीय आरियों का प्रतिविधियां और पुनर्निर्माण तथा प्रतिविधि वित्त प्रबन्धन अधिनियम, 2002 के धारा 13 (2) के अन्य निवारणी विधि के एक सूचना उनके द्वारा बैठक के उपलब्ध कराया गया, उनके अधिनियम जारी कर दिया गया। इस सार्वजनिक सूचना द्वारा सूचित किया जा रहा है।

जून से पहले शासन के अनुमोदन के लिए भेजा जाना

सार्वजनिक सूचना

पंजी. कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, लैंडमार्क, रेस कोर्ट सॉफ्टकॉर्न,

कापार्ट-1 कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टावर, बान्दा-कूला कॉम्प्लेक्स, बान्दा (ई), यूपी-400051

शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टावर, सेक्टर-11, काम्प्लेक्स सेंटर एस.एस. टावर, सेक्टर-8, रोहिंगी, नई दिल्ली-110085

एस्टेट्स शूपानी द्वारा भी होती है कि निर्माणित कर्जदारी/रोड एंपैक्स द्वारा नियम 5 के उप-नियम (2क) के साथ परियोजना की योजना नहीं की उप-धारा (4) के तहत सामने आयी है।

नगर निगम आपसी सहमति पर चर्चा चल रही है। बैठक बुलाने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। बोर्ड

विपक्ष की भी भागीदारी होनी चाही रही। उनका मानना है कि नगर निगम में सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर काम की पहली बैठक किसी भी सुरक्षा में 23 जून तक होनी चाही है। उनको वित्तीय आरियों का प्रतिविधियां और पुनर्निर्माण तथा प्रतिविधि वित्त प्रबन्धन अधिनियम, 2002 के धारा 13 (2) के अन्य निवारणी विधि के एक सूचना उनके द्वारा बैठक के उपलब्ध कराया गया, उनके अधिनियम जारी कर दिया गया। इस सार्वजनिक सूचना द्वारा सूचित किया जा रहा है।

जून से पहले शासन के अनुमोदन के लिए भेजा जाना

सार्वजनिक सूचना

पंजी. कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, लैंडमार्क, रेस कोर्ट सॉफ्टकॉर्न,

कापार्ट-1 कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टावर, बान्दा-कूला कॉम्प्लेक्स, बान्दा (ई), यूपी-400051

शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टावर, सेक्टर-11, काम्प्लेक्स सेंटर एस.एस. टावर, सेक्टर-8, रोहिंगी, नई दिल्ली-110085

गर्मी का प्रकोप

24 घंटे अलर्ट रहे प्रशासनिक मशीनरी

पायनियर समाचार सेवा | लखनऊ

मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने नमामि गणे एवं जलाधारी विभाग के अन्तर्गत जल जीवन मिशन, अटल भूजल व नमामि गणे योजना के समीक्षा की। मुख्य सचिव ने इस पर कठा कि प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत तेजी से कार्य हो रहा है, यह सराहनीय है।

आगे भी इसी तरह का प्रदर्शन जारी रहे। जिन जनपदों में रोड फिलिंग और रोड कटिंग की समस्याएं आ रही हैं एवं उनका नियन्त्रण जल्द करा लिया जाए। नमामि गणे योजना के तहत प्रयागराज में जो कार्य हो रहे हैं उन्हें महाकृष्ण-2025 से पूर्व पूरा करा लिया जाए।

उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से गर्मी का प्रकोप अधिक है, अतः इसके दृष्टिगत प्रत्येक उन्होंने में समस्त जनपदों में सम्बन्धित प्रशासनिक मशीनरी 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखे। प्रदेश के समस्त



जनपदों में नामित नोडल अधिकारियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्याओं की सूचना प्राप्त कर उनका तत्वत्त्व समाधान कराया जाये। जनपद सरकार के नोडल अधिकारी का मोबाइल नंबर एवं कंट्रोल रूम के नम्बर अनिवार्य रूप से तहसीली, विकास खण्डों, ग्राम पंचायतों आदि में प्रासारित किया जाये। उत्तर युग्मता के लिए प्रत्येक ग्राम में चर्चायत की गुणवत्ता का नाम जाल योजना को चर्चायत की गुणवत्ता के लिए प्रत्येक ग्राम में चर्चायत की गुणवत्ता को चर्चायत की गुणवत्ता की जांच के परिणामों को जेजेम डब्ल्यूएमआईएस पोर्टेल पर

अवश्य अपलोड कराया जाए। उन्होंने अलर्ट भूजल (अटल जल) योजना में उत्तर युग्मता को भारत सरकार से मिले इंसेटिक्स के यूटलाइजेशन में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर प्रसन्न व्यक्त करते हुए उत्तर युग्मता की अधिकारियों का उत्तरवाहन किया। उत्तर प्रदेश ने 7 राज्यों की रैंकिंग में युग्मता, हारियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, अंगरेजी और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को प्रत्येक ग्राम स्थान पर योजना की गोपनीयता देकर प्रशासनिक मशीनरी 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखे। प्रदेश के समस्त

जिले लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जून के शुरुआती 14 दिनों के बीच सर्वेक्षण की स्थिति का अंकलन करें तो बेस्ट रफरफार्मेंस करने वाले जिलों में यूपी सर्वे आगे है। 75,100 प्रतिशत तक टैप कनेक्शन करवें और ज्ञासी जिले साथ मिल हैं। जबकि फर्स्टर मूविंग जिलों में जालौन, गोपन्मुद्रनगर और शाहजहांपुर जिलों ने 50-75 टैप प्रतिशत तक टैप कनेक्शन करवें और अचीवर्स की रैंकिंग हासिल की है। 14 जून तक 50 प्रतिशत हाउस हॉल्ड्स टैप वाटर कनेक्शन के स्टेटस में 267,274 अक के साथ उत्तर प्रदेश नंबर वन रैंक पर है। अब तक 26621624 लक्ष्य के सापेक्ष 12639557 घरों को टैप वाटर सपाई बनाया जाता है। जून तक 10 जिलों—जालौन, गोपन्मुद्रनगर, मेरठ, चित्रकूट, बागपुर, मिर्जापुर, बांदा, जासों, ललितपुर एवं महावा में 75,100 प्रतिशत के मध्य कार्य हो चुके हैं।



सीजन योगी ने अपने सचिवाली आवास पर संकृति राजगांव सिविति के सदस्यों से शिष्टाचार नेट की

पुलिस कर्मियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने को धनराशि स्वीकृत

● 35वीं गाहिनी पीएसी, लखनऊ में बनेगा 150 खिलाईयों की थामता का एक मल्टीस्टोरी स्पोर्ट्स हॉटल

पायनियर समाचार सेवा | लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपदों में तैयार पुलिस कर्मियों के लिए आवासीय भवनों एवं आवासीय भवनों के व्यापक उपलब्धी के लिए अधिकारी व्यापक उपलब्धी के लिए 1 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक की धनराशि धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

संजय प्रसाद ने बताया कि जनपदों में तैयार पुलिस कर्मियों के लिए आवासीय भवनों के व्यापक उपलब्धी के लिए 1 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक की धनराशि धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। प्रसाद ने बताया कि जनपदों में तैयार पुलिस कर्मियों के लिए 1 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक की धनराशि धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

पुलिस कर्मियों के लिए 1 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक की धनराशि धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

पुलिस कर्मियों के लिए 1 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक की धनराशि धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

पुलिस कर्मियों के लिए 1 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक की धनराशि धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

पुलिस कर्मियों के लिए 1 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक की धनराशि धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

पुलिस कर्मियों के लिए 1 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक की धनराशि धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

पुलिस कर्मियों के लिए 1 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक की धनराशि धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

पुलिस कर्मियों के लिए 1 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक की धनराशि धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

पुलिस कर्मियों के लिए 1 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक की धनराशि धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

पुलिस कर्मियों के लिए 1 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक की धनराशि धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

पुलिस कर्मियों के लिए 1 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक की धनराशि धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

पुलिस कर्मियों के लिए 1 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक की धनराशि धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

पुलिस कर्मियों के लिए 1 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक की धनराशि धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

पुलिस कर्मियों के लिए 1 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक की धनराशि धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

पुलिस कर्मियों के लिए 1 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक की धनराशि धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

पुलिस कर्मियों के लिए 1 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक की धनराशि धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

पुलिस कर्मियों के लिए 1 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक की धनराशि धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

पुलिस कर्मियों के लिए 1 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक की धनराशि धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

पुलिस कर्मियों के लिए 1 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक की धनराशि धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

पुलिस कर्मियों के लिए 1 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक की धनराशि धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

पुलिस कर्मियों के लिए 1 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक की धनराशि धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

पुलिस कर्मियों के लिए 1 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक की धनराशि धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

पुलिस कर्मियों के लिए 1 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक की धनराशि धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

पुलिस कर्मियों के लिए 1 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक की धनराशि धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

पुलिस कर्मियों के लिए 1 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक की धनराशि धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

पुलिस कर्मियों के लिए 1 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक की धनराशि धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

पुलिस कर्मियों के लिए 1 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक की धनराशि धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

पुलिस कर्मियों के लिए 1 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक की धनराशि धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

पुलिस कर्मियों के लिए 1 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक की धनराशि धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

पुलिस कर्मियों के लिए 1 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक की धनराशि धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

पुलिस कर्मियों के लिए 1 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक की धनराशि धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

पुलिस कर्मियों के लिए 1 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक की धनराशि धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

पुलिस कर्मियों के लिए 1 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक की धनराशि धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

पुलिस कर्मियों के लिए 1 करोड़ 6

